

‘लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ के लिये 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान

चर्चा में क्यों?

25 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ के लिये 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब योजना के सुगम संचालन में सहायता मिलेगी तथा लाभार्थियों का दायरा बढ़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा छोटे व्यवसायियों एवं नविशकर्त्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये लाई गई ‘मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना’ के लिये 150 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी थी।
- इस योजना के लिये पूर्व में ही लगभग 58 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इसके लिये प्रावधति बजट में वृद्धि की गई है।